



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 10, 1971 (आषाढ़ 19, 1893)

No. 28]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 10, 1971 (ASADHA 19, 1893)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस

(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 8 फरवरी 1971 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to 8th February 1971 :—

अंक (Issue No.)	संख्या और तिथि (No. and date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)
1	2	3	4

शून्य  
-NIL-

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियाँ प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएगी।  
मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुँच जाने चाहिए।

Copies of the Gazette Extraordinary mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

M141GI/71

(601)

## विषय-सूची

भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	601	भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)— रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	3531
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	955	भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	427
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	69	भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	855
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	773	भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें	245
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—	भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	91
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—	भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं	1813
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	2551	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें	129
		पूरक संख्या 27—	
		26 जून 1971 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्टें	1097
		5 जून 1971 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े	1113

## CONTENTS

PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	601	PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	3531
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	955	PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	427
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	69	PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	855
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	773	PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	245
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—	PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	91
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—	PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1813
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, by-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	2551	PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	129
		SUPPLEMENT No. 27	
		Weekly Epidemiological Reports for weeks ending 26th June 1971	1097
		Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 5th June 1971	1113

## भाग I—खण्ड 1

## (PART I—SECTION 1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

## राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 जुलाई 1971

सं० 33-प्रेज/71—राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के निम्नांकित अधिकारी को उस की वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री गोविन्द अप्पुकुट्टन,  
कांस्टेबल सं० 61110134,  
11वीं बटालियन,  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

24 दिसम्बर, 1970 को प्रातः एक गश्ती दस्ते को नागालैंड में पुंगलोमी गांव की तलाशी लेने के लिए निदेश दिया गया। गांव का घरा डालने के पश्चात् पुलिस दल को उन घरों की तलाशी लेने को तैनात किया जिनमें विरोधियों के छुपने का सन्देह था। श्री गोविन्द अप्पुकुट्टन और सात अन्य कांस्टेबलों का एक पुलिस दल जब विरोधियों के एक भूतपूर्व हवलदार के घर पहुँचा तो मकान के निवासियों ने दरवाजा बन्द कर लिया। परन्तु पुलिस दल ने बलपूर्वक मकान में प्रवेश किया और तलाशी लेनी शुरू की। तलाशी के दौरान श्री अप्पुकुट्टन ने देखा कि मकान के निवासी सोने का बहाना बना रहे हैं। श्री अप्पुकुट्टन उनकी चाल को समझ गया और उसने उनके कम्बल खींचे। फिर उसे कम्बल से ढकी बड़ी टोकरी के नीचे से राईफल के बोल्ट का धीरे से ठीक करने की आवाज आई। उसने कम्बल को हटाया और विरोधी को पकड़ लिया जो टोकरी के नीचे छिपा हुआ था। विरोधी ने राईफल श्री अप्पुकुट्टन की छाती पर दबा दी, किन्तु अप्पुकुट्टन ने निशाना नली राईफल को एक ओर हटा दिया और अपनी राईफल का हत्या विरोधी को मारा। फिर अपनी सुरक्षा की बिल्कुल परवाह न करते हुए विरोधी के साथ वह गुथमगुथा हो गया। कड़े संघर्ष के बाद श्री अप्पुकुट्टन ने उसकी राईफल छीन ली। इस मुकाबले में श्री अप्पुकुट्टन ने विरोधी को, जो एक मुख्य विरोधी नेता था, पकड़ने में साहस तथा दृढ़ संकल्प का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी 24 दिसम्बर 1970 से दिया जायेगा।

नारोन्द्र सिंह, राष्ट्रपति के सचिव

## लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 21 जून 1971

सं० 5/1/71/पी० ए० सी०—लोक सभा और राज्य-सभा के निम्नलिखित सदस्य, 30 अप्रैल, 1972 को समाप्त होने वाली कार्यावधि के लिए, लोक लेखा समिति के सदस्य निर्वाचित किये गये हैं:—

## लोक-सभा के सदस्य

1. श्री भागवत झा आजाद
2. श्रीमती मुकुल बनर्जी
3. श्री सी० सी० देसाई
4. श्री के० जी० देशमुख
5. चौधरी तैयब हुसैन खां
6. श्री डी० एन० महाता
7. श्री मुहम्मद युसूफ
8. श्री बी० एस० मूर्ति
9. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डे
10. श्री राम सहाय पाण्डे
11. श्रीमती सावित्री श्याम
12. श्री इरा सेक्षियान
13. श्री विजय पाल सिंह
14. श्री जी० वेंकटस्वामी
15. श्री रामचन्द्र विकल

## राज्य-सभा के सदस्य

16. श्री एस० बी० बोबडे
17. श्री बी० के० कौल
18. श्री निरंजन वर्मा—(समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया)
19. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी
20. श्री तिल्लड बिल्ललन
21. श्री श्याम लाल यादव
22. श्री शील भद्र याजी

2. अध्यक्ष महोदय ने श्री इरा सेक्षियान को सहर्ष समिति का सभापति नियुक्त किया है।

बी० बी० तिवारी, उप सचिव

नई दिल्ली-1, दिनांक 22 जून 1971

सं० 3/1/ई० सी० -दो/71—अध्यक्ष महोदय ने श्री कमलनाथ तिवारी को 30 अप्रैल, 1972 को समाप्त होने वाली कार्यविधि के लिए प्राक्कलन समिति का सभापति नियुक्त किया है।

एम० एस० सुन्नेसन, उप सचिव

**मंत्रिमंडल सचिवालय  
(कार्मिक विभाग)**

नई दिल्ली-1, दिनांक 10 जुलाई 1971

सं० 5/18/71—सी० एस० (1) केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1972 में ली जाने वाली सोमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के नियम सर्व साधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

2. चयन सूची में शामिल करने के लिए प्रवरण किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी की जाने वाली सूचना में निर्दिष्ट की जायगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्त स्थानों के संबंध में आरक्षण इस प्रकार किये जायेंगे जैसा सरकार द्वारा निश्चित किया जाय।

अनुसूचित जातियों /अनुसूचित आदिम जातियों का अर्थ किसी भी जाति आदिम जाति का संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (भाग ग राज्य) आदेश, 1951, संविधान (आदिम जाति) आदेश 1950 और संविधान (आदिम जाति (भाग ग) राज्य) आदेश, 1951 जोकि समय समय पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति सूची (संशोधन) आदेश 1956 से संशोधित किया गया और जो बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, 'संविधान (जम्मू तथा कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 संविधान (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962 संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962 संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति (उत्तर प्रदेश), आदेश, 1967, संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968 तथा संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968 और संविधान (नागालैंड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश 1970 के साथ पठित अनुसूचित जाति। आदिम जाति सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956 में उल्लिखित जातियों/आदिम जातियों में से कोई सी जाति है।

3. इन नियमों के परिशिष्ट में निर्धारित पद्धति के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा ली जायगी।

किस तारीख को और किन-किन स्थानों पर परीक्षा ली जायगी, इसका निश्चय आयोग करेगा।

4. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों की श्रेणी का कोई भी स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अधिकारी, जो 1 जुलाई, 1971 को निम्नलिखित शर्तें पूरा करता हो, इस परीक्षा में बैठने का पात्र होगा:—

**सेवा-अवधि**

उसने निम्नलिखित पदों में से किसी एक अथवा एक से अधिक पदों में, जैसी भी स्थिति हो, कम से कम 5 वर्ष की लगातार सेवा की हो, अर्थात्:—

(I) सहायक (केन्द्रीय सचिवालय सेवा)

(II) केन्द्रीय सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों सहित अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद जिसके वेतन-मान की न्यूनतम और अधिकतम राशि 1 जुलाई, 1959 से पहले धारित किसी पद के मामले में क्रमशः 160 रु० और 450 रु० से कम और 1 जुलाई, 1959 को या उसके बाद में धारित किसी पद के मामले में क्रमशः 210 रु० और 530 रु० से कम न हो।

टिप्पणी:—केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों की श्रेणी का कोई स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अधिकारी, जिसने 26 अक्टूबर, 1962 को जारी की गई आपात्काल की उद्घोषणा के प्रवर्तन काल में, अर्थात् 26 अक्टूबर, 1962 से 9 जनवरी, 1968 तक सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि प्रशिक्षण की अवधि को मिलाकर, सेवा की हो, सशस्त्र सेना से प्रत्यावर्तन पर सशस्त्र सेना में यदि कोई हो निर्धारित न्यूनतम सेवा में गिन सकेगा।

(2) आयु:—(क) उसकी आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात् 1 जुलाई, 1931 से पहले उसका जन्म न हुआ हो।

परन्तु उपरोक्त नियम 4(1) में उल्लिखित किसी एक अथवा एक से अधिक, जैसी भी स्थिति हो, पदों में काम करने वाला

(1) कोई उम्मीदवार जिसका जन्म 1 जुलाई, 1931 से पहले किन्तु 1 जुलाई, 1930 से पहले न हुआ हो तथा जिसने 1 जुलाई, 1970 को कम से कम पांच वर्ष की निरन्तर सेवा कर ली हो, और

(2) कोई उम्मीदवार जिसका जन्म 1 जुलाई, 1930 से पहले किन्तु 1 जुलाई, 1929 से पहले न हुआ हो तथा जिसने 1 जुलाई, 1969 को कम से कम पांच वर्ष की निरन्तर सेवा कर ली हों;

भी विशेष मामले में रूप में इस परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र होगा। यह छूट केवल 1972 में ली जाने वाली परीक्षा के लिए लागू होगी।

टिप्पणी:—(क) 40 वर्ष की आयु सीमा केवल इस परीक्षा के लिए लागू है।

(ख) ऊपर निर्धारित आयु सीमा में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों की श्रेणी के उन स्थायी अथवा नियमित रूप में नियुक्त अस्थायी अधिकारियों के मामलों में, जिन्होंने 26 अक्टूबर, 1962 को जारी की गई आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन काल में अर्थात् 26 अक्टूबर, 1962 से 99 जनवरी, 1968 तक सशस्त्र सेना में नौकरी की और जो वहाँ से प्रत्यावर्तित हो गए हों, सशस्त्र सेना में अपनी सेवा (प्रशिक्षण अवधि समेत, यदि कोई हो) की अवधि तक की छूट दी जायगी।

(ग) ऊपर निर्धारित आयु सीमा में निम्नलिखित मामलों में और अधिक छूट दी जायगी:—

(I) यदि कोई उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति अथवा किसी अनु० आदिम जाति से संबंधित हो तो अधिकतम पांच वर्ष तक।

(II) यदि कोई उम्मीदवार पूर्वी पाकिस्तान से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और उसने 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद भारत को प्रव्रजन किया हो तो अधिकतम तीन वर्ष तक;

(III) यदि कोई उम्मीदवार किसी अनु० जाति से संबंधित हो और पूर्वी पाकिस्तान से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और उसने 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद भारत को प्रव्रजन किया हो तो अधिकतम आठ वर्ष तक;

(IV) यदि कोई उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र पाण्डिचेरी का निवासी हो और किसी अवस्था पर उसने फ्रांसिसी भाषा के माध्यम से शिक्षा पाई हो तो अधिकतम तीन वर्ष तक

(V) यदि कोई उम्मीदवार श्रीलंका से भारतीय मूल का वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो और अक्टूबर, 1964 के भारत-लंका समझौते के अधीन उसने 1 नवम्बर, 1964 को अथवा उसके बाद भारत को प्रव्रजन किया हो तो अधिकतम तीन वर्ष तक;

(VI) यदि कोई उम्मीदवार किसी अनु० जाति अथवा अनु० आदिम जाति से सम्बन्धित हो और श्रीलंका से भारतीय

मूल का वास्तविक देश प्रत्यावर्तित व्यक्ति भी हो और अक्टूबर, 1964 के भारत-लंका समझौते के अधीन उसने 1 नवम्बर, 1964 को अथवा उसके बाद भारत को प्रव्रजन किया हो तो अधिकतम आठ वर्ष तक;

(VII) यदि कोई उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और उसने कैम्या, उगाण्डा अथवा तंजानिया संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका तथा जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो तो अधिकतम तीन वर्ष तक;

(VIII) यदि कोई उम्मीदवार बर्मा के भारतीय मूल का वास्तविक देश प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो और उसने 1 जून, 1963 को अथवा उसके बाद भारत को प्रव्रजन किया हो तो अधिकतम तीन वर्ष तक;

(IX) यदि कोई उम्मीदवार अनु० जाति अथवा अनु० आ० जाति से सम्बन्धित हो और बर्मा से भारतीय मूल का वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित व्यक्ति भी हो और उसने 1 जून, 1963 को उसके बाद भारत को प्रव्रजन किया हो तो अधिकतम आठ वर्ष तक;

(X) प्रतिरक्षा सेवा कर्मचारियों के मामले में जो किसी बाहरी देश के साथ संघर्ष के दौरान सैनिक कार्यवाही में अथवा किसी उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में अशक्त हो गया हो और उसके परिणामस्वरूप सेवा-मुक्त कर दिया गया हो तो अधिकतम तीन वर्ष तक;

(XI) प्रतिरक्षा सेवा कर्मचारियों के मामले में जो अनु० जाति अथवा अनु० आदिम जाति से सम्बन्धित हो तथा जो किसी बाहरी देश के साथ संघर्ष के दौरान सैनिक कार्यवाही में अथवा किसी उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में अशक्त हो गया हो और उसके परिणामस्वरूप सेवा-मुक्त कर दिया हो तो अधिकतम आठ वर्ष तक; और

(XII) यदि कोई उम्मीदवार गोवा, दमन, व दीव का निवासी हो तो अधिकतम तीन वर्ष तक।

उपयुक्त व्यवस्था के अतिरिक्त किसी भी दशा में निर्धारित आयु सीमा से छूट नहीं दी जा सकती है।

टिप्पणी 1:—वे सहायक जो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से से संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं, यदि अन्यथा पात्र हों, तो इस परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र होंगे।

किन्तु यह शर्त उस सहायक पर लागू नहीं होती जो किसी निःसर्वग पद अथवा किसी अन्य सेवा में स्थानान्तरण के आधार पर नियुक्त कर लिया गया हो और सहायकों की श्रेणी में उसका कोई धारणाधिकार न हो।

टिप्पणी-2—केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वे सहायक जिन्होंने भारतीय विदेश सेवा (ख) में नियुक्ति के लिए विकल्प दिया हो और ऐसे विकल्प के अनुसरण में उस सेवा की किसी श्रेणी में नियुक्ति कर लिए गये हों, इस परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी 3—किसी अनुसूचित जाति के ऐसे सहायक के मामले में, जिसे 14 अप्रैल, 1962 से 30 अप्रैल, 1964 तक की अवधि में पदोन्नति की “मान ली गई” तारीख का लाभ देकर तदर्थ पदोन्नति दी गई हो, उपर्युक्त नियम के प्रयोजन के लिए सहायकों की श्रेणी में सेवा की अवधि की संगणना करने के लिए सहायक के रूप में उसकी पदोन्नति की वास्तविक तारीख पर ही विचार किया जायगा।

5. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

6. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जायगा जब तक उसके पास आयोग का प्रवेश पत्र न हो।

7. यदि कोई उम्मीदवार आयोग द्वारा इस बात के लिए दोषी घोषित किया जाय या किया गया हो कि उसने दूसरे व्यक्ति से अपनी परीक्षा दिलवाई है या जाली प्रलेख अथवा ऐसे प्रलेख प्रस्तुत किए हैं जिनमें कि हेराफेरी की गई है या गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या कोई महत्वपूर्ण बात छिपाई है या परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित या अनुपयुक्त तरीके से काम लिया है अथवा परीक्षा भवन में अनुचित तरीकों का प्रयोग किया है या प्रयोग करने की कोशिश की है या परीक्षा भवन में कोई दुर्व्यवहार किया है, तो उस पर आपराधिक अभियोग चलाए जाने के अतिरिक्त:—

(क) आयोग उसे उम्मीदवारों के चुनाव के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा में बैठने या किसी भी इंटरव्यू में शामिल होने संस्थायी रूप से अथवा किसी विशिष्ट अवधि के लिए रोक सकता है; और

(ख) उपयुक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

8. यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो उसे उक्त परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

9. उम्मीदवारों को आयोग के नोटिस के परिशिष्ट 1 में निर्धारित फीस देनी होगी।

10. परीक्षा के बाद, अंतिम रूप से प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए कुल अंकों के आधार पर आयोग योग्यता-क्रम से उम्मीदवारों की सूची बनाएगा, और उसी क्रम से जितने उम्मीदवार परीक्षा द्वारा अर्हक कि समझे जायेंगे, उनको अपेक्षित संख्या तक अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में शामिल करने के लिए सिफारिश करेगा।

परन्तु यदि किसी अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति का कोई उम्मीदवार आयोग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार अर्हता प्राप्त न करने पर भी यदि प्रशासन की कुशलता बनाए रखने की बात पर उचित ध्यान देते हुए अनुभाग अधिकारियों की श्रेणी के लिए चयन सूची में शामिल किये जाने के लिए उपयुक्त घोषित कर दिया जाय, तो यथास्थिति, अनुसूचित जातियों अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित संख्या तक उसमें शामिल किये जाने के लिये उसकी सिफारिश की जायेगी।

टिप्पणी:—उम्मीदवारों को यह स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए कि उम्मीदवारों को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए, कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है, न कि अर्हक परीक्षा। परीक्षा के परिणाम के आधार पर अनुभाग अधिकारियों की श्रेणी की चयन सूची में शामिल किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या नियत करने के लिए सरकार पूरी तरह से सक्षम है। इसलिए कोई उम्मीदवार इस परीक्षा में अपने निष्पादन के आधार पर चयन सूची में शामिल किये जाने के लिए अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकेगा।

11. हर एक उम्मीदवार को परीक्षा-फल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाय, इसका निर्णय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा और आयोग परिणामों के सम्बन्ध में उनसे कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

12. जब तक यथावश्यक जांच के बाद सरकार इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार चयन के लिए हर प्रकार से पात्र तथा उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में पास हो जाने मात्र से ही चयन किये जाने का कोई अधिकार नहीं मिल सकेगा।

अपितु द्वारा चयन किये जाने के लिए सिफारिश किये गए किसी उम्मीदवार को चयन के लिए अपात्र मानने के बारे में निर्णय आयोग के साथ परामर्श करके किया जायगा।

13. यदि कोई उम्मीदवार, परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र भेजने के बाद अथवा परीक्षा में बैठने के बाद केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अपनी नियुक्ति से त्यागपत्र दे दे, अथवा और किसी कारणवश सेवा छोड़ अथवा उसके सम्बन्ध में विच्छेद कर ले, अथवा उसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी जाय अथवा वह किसी संवर्ग बाह्य पद पर अथवा अन्य सेवा में “स्थानान्तरण” पर नियुक्त किया जाय और

सहायक की श्रेणी पर उसका पुनर्ग्रहणाधिकार नहीं रहे, तो वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यह बात उस सहायक के मामले में लागू नहीं होगी जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पद पर प्रतियुक्ति पर नियुक्त किया गया है।

14. जिन उम्मीदवारों ने 26 अक्टूबर, 1962 को जारी की गई आपात्काल की उद्घोषणा के प्रवर्तन काल में अर्थात् 26 अक्टूबर, 1962 से 9 जनवरी, 1968 तक सशस्त्र सेना में नौकरी की हो और जो सशस्त्र सेना में अपनी सेवावधि के दौरान ली गई अनुभाग अधिकारियों की श्रेणी की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (जो०) में न बैठ सके हो, यदि इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर अनुभाग अधिकारियों की श्रेणी की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए अंतिम रूप से उनकी सिफारिश की जाती है, तो उनकी वरिष्ठता भारत सरकार द्वारा जारी किये गये विशेष आदेशों के अनुसार नियंत्रित होगी।

के० एल० अरोरा, अवर सचिव

#### परिशिष्ट

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार ली जायगी:—  
भाग I—निम्नलिखित पैरा 2 में दिये गये विषयों में अधिक से अधिक 450 अंकों की लिखित परीक्षा।

भाग II —आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार यथानिश्चित उम्मीदवारों की सेवा के रिकार्ड का मूल्यांकन, जिसके अधिकतम 150 अंक होंगे।

2 भाग 1 में लिखित परीक्षा के विषय, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए दिया जाने वाला समय और आवंटित अधिकतम अंक उस प्रकार होंगे:—

विषय	अधिकतम अंक	दिया जाने वाला समय
		घण्टे
(1) टिप्पणी, मसौदा तथा सार लेखन	100	2½
(2) भारत सरकार सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में प्रक्रिया तथा पद्धति	100	2½
(3) भारतीय संविधान तथा सरकार के शासनतंत्र का सामान्य ज्ञान; संसदीय पद्धति तथा प्रक्रिया	100	2½
(4) सामान्य वित्तीय तथा सेवा नियम	50	1½
(5) सामान्य ज्ञान	100	2½

3. परीक्षा का पाठ्य-विवरण इस परिशिष्ट की अनुसूची में बतलाए गए अनुसार होगा।

जहां नियमों, आदेशों अनुदेशों इत्यादि का ज्ञान अपेक्षित है वहां उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाएगी कि वे इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख तक जारी किये गये संशोधनों से परिचित हों।

4. उभी प्रश्न-पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में देने होंगे।

5. उम्मीदवारों को उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किन्हीं भी परिस्थितियों में उन्हें उत्तर लिखने के लिए लिपिक की सहायता की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. आयोग अपने विवेकानुसार परीक्षा के किसी विषय अथवा सभी विषयों के अर्हक अंक निर्धारित करेगा।

7. केवल सतही ज्ञान के लिए कोई अंक नहीं दिये जाएंगे।

8. अस्पष्ट लिखावत के लिए लिखित विषयों में अधिकतम अंकों के पांच प्रतिशत अंक तक काट लिए जाएंगे।

9. परीक्षा के सभी विषयों में कमबद्ध, प्रभावी तथा यथार्थ और साथ ही साथ कम से कम शब्दों में अभिव्यक्ति के लिए मान्यता दी जाएगी।

#### अनुसूची

##### परीक्षा का पाठ्य-विवरण

(1) टिप्पणी तथा मसौदा लेखन, सार-लेखन;

ऐसे प्रश्नों के अतिरिक्त जिनमें उम्मीदवारों से विशिष्ट समस्याओं पर टिप्पणियां तथा मसौदे तैयार करने को कहा जाएगा, सारांश तथा सार-लेखन के लिए परिच्छेद भी दिये जा सकते हैं:

(2) भारत सरकार सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में प्रक्रिया तथा कार्य-पद्धति।

इसका उद्देश्य भारत सरकार सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में प्रक्रिया तथा कार्य-पद्धति की वृहत् तथा विस्तृत परीक्षा लेना है। इस विषय में कुछ मार्गदर्शन निम्नलिखित पुस्तकों आदि से प्राप्त किया जा सकता है:—

अधिसूचना जारी किये जाते समय प्रचलित कार्यालय पद्धति ;

(3) सरकार के शासन तंत्र तथा भारतीय संविधान का सामान्य ज्ञान संसदीय प्रक्रिया तथा कार्य-पद्धति।

टिप्पणी निम्नलिखित का ज्ञान होने की आशा की जाएगी :

(i) भारतीय संविधान के मुख्य सिद्धांत;

(ii) लोक सभा तथा राज्य सभा में कार्य संचालन तथा प्रक्रिया सम्बन्धी, नियम, तथा

(iii) भारत सरकार के शासन-तंत्र का गठन—मंत्रालयों, के बीच विषयों का विवरण तथा आवंटन विभागों तथा संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में पदों का परस्पर संबंध

(4) सामान्य वित्तीय तथा सेवा नियम।

निम्नलिखित पुस्तकों की सिफारिश की जाती है:—

(i) मूल तथा पूरक नियम (डाक तथा तार के महालेखाकार) का संकलन

(ii) सिविल सेवा विनियम (केवल पेंशन वाला भाग)

- (III) केन्द्रीय सिविल सेवा (आवरण) नियम, नियम, 1964
- (IV) केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपोल) नियम, 1965
- (V) सामान्य वित्तीय नियम (पुनरांकित तथा परिवर्तित) 1963 का संकलन।
- (VI) वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1958 (भारत सरकार के निर्णयों समेत) का संकलन तथा 1 जून, 1962 के प्रत्यायोजन आदेश।

### सामाज्य ज्ञान

इस प्रश्न-पत्र में सामयिक महत्व तथा रुचि के विषय सम्मिलित होंगे। पंचवर्षीय योजनाओं तथा सामुदायिक विकास योजनाओं की विस्तृत तथा मुख्य बातों के ज्ञान तथा राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों से सम्बन्धित सामयिक घटनाओं की ऐसी बुद्धिमत्तापूर्ण जानकारी, जो किसी शिक्षित व्यक्ति को होनी चाहिए, की परीक्षा के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। उम्मीदवारों के उत्तरों से यह प्रकट होने की आशा की जाती है कि वे प्रश्नों को अच्छी तरह समझते हैं न कि उन्हें किन्हीं पाठ्य-पुस्तकों, प्रतिवेदनों इत्यादि का व्यापक ज्ञान है।

(भूतपूर्व पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय (खान और धातु विभाग) के संकल्प संख्या जे-11014/1/70-खान-1 तारीख 2 फरवरी 1971 को अधिक्रान्त करते हुए)

### इस्पात और खान मंत्रालय

#### (खान विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 जून 1971

#### संकल्प

सं० जे० 11014/1/70-खान I—केन्द्रीय भूवैज्ञानिक योजना-करण बोर्ड की 10 सितम्बर, 1970 को हुई बैठक में यह विनिश्चय किया गया था कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, अन्य केन्द्रीय अभिकरणों और राज्य विभागों के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में योजना उद्देश्यों पर अधिक विस्तार से विचार करने के लिए उप-समितियां गठित की जाएं। तदनुसार भारत सरकार ने निम्न-लिखित उप-समितियां गठित करने का विनिश्चय किया है, जिनका गठन इस प्रकार है :—

#### 1. अलौह धातुओं पर उप समिति :

1. उप महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (श्री एस० पी० नौटियाल) संयोजक
2. नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो
3. हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड का प्रतिनिधि
4. हिन्दुस्तान जस्ता लिमिटेड का प्रतिनिधि
5. निदेशक, खनन और भूविज्ञान, राजस्थान
6. निदेशक, खनन और भूविज्ञान, आंध्र प्रदेश
7. निदेशक, खनन और भूविज्ञान, मैसूर
8. खनन सलाहकार - श्री आई० एम० आगा

#### II. (कोयला को छोड़कर) लौह और इस्पात के लिए खनिजों पर उप-समिति :

1. उपमहानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (डा० एस० बी० पी० आयरंगर) संयोजक
2. नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो
3. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का प्रतिनिधि
4. निदेशक, खनन और भूविज्ञान, बिहार
5. निदेशक, खनन और भूविज्ञान, मध्य प्रदेश
6. निदेशक, खनन और भूविज्ञान, उड़ीसा
7. खनन सलाहकार - श्री आई० एम० आगा

#### III. भूजल पर उप-समिति :

1. उप-महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (श्री बी० सुब्रमण्यम्) संयोजक
2. मुख्य समन्वेषी नलकूप संगठन का प्रतिनिधि
3. श्री आर० एन० पी० आरोग्यास्वामी, मुख्य (खनिज) योजना आयोग
4. निदेशक, खनन और भूविज्ञान, महाराष्ट्र
5. निदेशक, खनन और भूविज्ञान, उत्तर प्रदेश
6. निदेशक, खनन और भूविज्ञान, हरियाणा

#### (IV) अन्य खनिजों पर उप-समिति

1. उप-महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (श्री सी० कूरणाकरण) संयोजक
2. नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो
3. निदेशक, खनन और भूविज्ञान, तमिलनाडु
4. निदेशक, खनन और भूविज्ञान, गुजरात
5. भूविज्ञानविद, उद्योग निदेशालय, पंजाब, चंडीगढ़
6. निदेशक, भूविज्ञान, केरल
7. खनन सलाहकार - श्री आई० एम० आगा

#### (V) कोयले पर उप-समिति :

1. महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का प्रतिनिधि (श्री बी० लस्कर) संयोजक
2. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का प्रतिनिधि
3. केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान का प्रतिनिधि
4. निदेशक, खनन और भूविज्ञान, बिहार
5. निदेशक, खनन और भूविज्ञान, असम
6. निदेशक, खनन और भूविज्ञान, पश्चिमी बंगाल
7. निदेशक, खनन और भूविज्ञान, मध्य प्रदेश
2. प्रत्येक उप-समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे :—

(i) देश में खनिजों के समन्वेषण से संबंधित अब तक किए गए कार्य का पुनर्विलोकन;

(ii) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, अन्य केन्द्रीय अभिकरणों और राज्य विभागों के विभिन्न कार्यक्रमों पर विचार करना;



(iii) यदि आवश्यक हो तो, कार्य की विभिन्न मदों को समनुदेशित प्राथमिकताओं में परिवर्तनों के लिए सिफारिश करना;

(iv) नीति और निष्पादन के विभिन्न आवश्यक मामलों पर समय-समय पर सरकार को परामर्श देना ।

3. (वांछनीय प्रतीत होने की सीमा तक अन्य उप-समितियों के सदस्यों को सम्मिलित कर) उप-समितियों को यह शक्ति होगी कि वे उस सीमा तक अन्य सदस्यों को सहयोजित कर सकेंगी जिस सीमा तक वे विचार विमर्श के दौरान आवश्यक समझें ।

4. अगले वर्ष उप-समितियों के कार्य को देखने के उपरान्त यदि यह आवश्यक हो तो, पश्चात्तर्वर्ती वर्षों में उप-समितियों की संरचना में चक्रानुक्रम द्वारा तथा नए हितबद्धों को भी प्रतिनिधित्व देते हुए उचित रूप से परिवर्तन किया जा सकेगा ।

5. उप-समितियाँ, केन्द्रीय भूवैज्ञानिक योजनाकरण बोर्ड की बैठक के बारे में अपनी रिपोर्टें खान विभाग को यथासमय पूर्व उपलब्ध कराएंगी ।

6. यह पहले जारी किए गए संकल्प सं० जे० 11014/1/70 खान-I, तारीख 2-2-1971 को अधिक्रान्त करता है ।

टी० एन० लक्ष्मीनारायणन, संयुक्त सचिव  
आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, समस्त राज्य सरकारों, संघ राज्य-क्षेत्रों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग तथा योजना आयोग सहित समस्त सम्पुक्तों को संसूचित की जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राज्यपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

टी० एन० लक्ष्मीनारायणन, संयुक्त सचिव

#### औद्योगिक विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 जून 1971

#### संकल्प

सं० 33(7)/71-एल० कन० इण्ड०—वातानुकूलन और प्रशीतन उद्योग की वृद्धि और विकास की आयोजना के लिए आवश्यक विशेष अभ्युपायों का परीक्षण करने और भारत सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से और इस क्षेत्र में निर्माताओं की विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए भारत सरकार ने इस उद्योग के लिये नामिका पुनर्गठित करने का निर्णय किया है । नामिका की संरचना निम्न प्रकार से होगी :—

1. श्री बी० पी० एस० मेनन, अध्यक्ष  
औद्योगिक सलाहकार,  
तकनीकी विकास का महानिदेशालय,  
नई दिल्ली

2. श्री डी० बी० मलिक, सदस्य-सचिव  
विकास अधिकारी,

तकनीकी विकास का महानिदेशालय,  
नई दिल्ली

3. श्री एस० राघवैया, सदस्य  
निदेशक,

विकास आयुक्त, लघु उद्योग का कार्यालय,  
नई दिल्ली

4. श्री एन० एन० अग्रवाल, सदस्य  
संयुक्त निदेशक, योजना आयोग,  
नई दिल्ली

5. श्री सुरेन्द्र एम० मेहता, सदस्य  
निदेशक, एयर कंट्रोल एण्ड कैमिकल इंजि०  
कं० लि०, रघुवंशी मिल्स कम्पाउंड,  
11-12, होस रोड, बम्बई-13

6. श्री राम डी० मलानी, सदस्य  
कार्यकारी निदेशक,  
ब्ल्यू स्टार लिमिटेड,  
जमशेदजी टाटा रोड, बम्बई-20

7. श्री पी० डी० गुने, सदस्य  
मुख्य कार्यकारी (संचालन)  
मे० किलोस्कर ब्रादर्स लि०,  
किलोस्कर वाडी, जिला सांगली,  
महाराष्ट्र

8. श्री जे० सी० कपूर, सदस्य  
निदेशक,  
मे० डनफोस (इं०) लिमिटेड,  
बी०-20/21, इंडस्ट्रियल एरिया  
साइट ० 3, मेरठ रोड, पो० बा० नं० 6,  
गाजियाबाद

9. श्री एम० सी० गुप्ता, सदस्य  
मे० श्रीराम रिफ्रीजेशन  
इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बालानगर टाउनशिप,  
हैदराबाद-37

10. श्री मनमोहन सिंह, सदस्य  
प्रबन्ध निदेशक,  
मे० फ्रिक इंडिया लिमिटेड,  
जीवन बिहार, 3- पालियामेंट स्ट्रीट  
पो० बा० नं० 118, नई दिल्ली

11. श्री जे० देसाई, सदस्य  
प्रबन्ध निदेशक,  
मे० कल्विनेटर आफ इन्डिया लि०,  
28, न्यू इंडस्ट्रियल टाउन, फरीदाबाद

12. श्री बी० पी० पुंज, सदस्य  
मे० फेंडर्स लायड कारपोरेशन  
प्रा० लि०, पुंज हाउस,  
एम०-13, कनाट सर्कस, नई दिल्ली

13. श्री ओ० पी० भातिया, सदस्य  
उप-प्रबन्धक निदेशक,  
मे० कटलर हैमर इंडिया लि०,  
20/4, मथुरा रोड, फरीदाबाद-11
14. श्री बी० एस० दुआ, सदस्य  
मे० अमेरिकन रिफ्रिजरेटर कं० लि०,  
12-डी०, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता-16
15. श्री एच० एल० स्पोन्सर, सदस्य  
प्रबन्ध निदेशक,  
मे० एस० एफ० इंडिया लिमिटेड,  
पो० बा० 411, कलकत्ता-1
16. श्री एन० बालासुब्रामनियन, सदस्य  
मे० वोल्तास लिमिटेड,  
19, ग्राहम रोड, बम्बई-1
17. श्री गजिन्द्र सिंह, सदस्य  
मे० ओरियन्टल रिफ्रिजेशन एण्ड इंजिनियरिंग  
कं० प्राइवेट लि०, लक्ष्मी बिल्डिंग, प्रथम फ्लोर,  
आमफ अली रोड, पो० ओ० वाक्स नं० 563,  
नई दिल्ली-1
18. श्री जी० के० कवरा, सदस्य  
चीफ इंजिनियर,  
मे० हैदराबाद आल्विन मेटल वर्क्स लि०,  
संतनगर, हैदराबाद-18
19. श्री अमर पी० सूर, सदस्य  
मे० सूर इंडस्ट्रीज प्रा० लि०,  
163, लोवर सरकुलर रोड, कलकत्ता
20. श्री रमेश आनन्द, सदस्य  
मे० चन्द्रा इंडस्ट्रीज,  
जी० टी० रोड, जलंधर
21. उप-निदेशक, सदस्य  
निरीक्षण, सीमा शुल्क और  
केन्द्रीय आबकारी, वित्त मंत्रालय,  
राजस्व और बीमा विभाग, नई दिल्ली
22. खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) सदस्य  
का एक प्रतिनिधि
23. श्री एम० बी० पाटनकर, सदस्य  
निदेशक (मेक० इंजी०) भारतीय मानक संस्था,  
मानक भवन, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली
24. सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च सदस्य  
इंस्टीट्यूट का एक प्रतिनिधि
2. नामिका का कार्यकाल दो साल के लिए होगा।

#### आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी सम्बन्धितों को भेजी जाये और आम सूचना के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

आर० के० तलवीर, संयुक्त सचिव

#### कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 मई 1971

#### संकल्प

सं० 30-1/71-पशुधन विकास III — इस मंत्रालय के संकल्प संख्या 30-1/71-पशुधन विकास-III दिनांक 2 फरवरी, 1971 के क्रम में तथा इस मंत्रालय के संकल्प संख्या 20-20/69-पशुधन विकास-III दिनांक 26/29-11-69 में आंशिक मंशोधन करते हुए, भारत सरकार ने निर्णय किया है कि प्रशासन निदेशक, विस्तार निदेशालय द्वारा केन्द्रीय गोसंवर्धन परिषद के करण्ट अकाउंट के संचालन की तिथि 31 मार्च, 1971 से 31 जुलाई, 1971 तक अथवा जब तक अनिर्णित किया जाता है, जो दायों का निर्णय कोई भी पहले हो, और आगे बढ़ाई जाती है।

#### आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प की एक प्रति सब राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा भारत सरकार के सब मंत्रालयों और विभागों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण की जानकारी के लिये यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

बी० पी० गुलाटी, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 19 जून 1971

#### संकल्प

सं० 19-9-71-पशु० वि० I—दिल्ली, मेरठ तथा बुलन्दशहर दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद नियंत्रण आदेश 1971 की प्रख्यापन के फलस्वरूप, भारत सरकार ने आदेश की अवधि, अर्थात् 7 मई 1971 से 15 जुलाई 1971 तक के लिये निम्नलिखित मदद्यों की एक मूल्य निर्धारण समिति गठित करने का निर्णय किया है:—

1. आयुक्त, मेरठ प्रभाग अध्यक्ष
2. अध्यक्ष, दिल्ली दुग्ध योजना सदस्य
3. उप सचिव (पशु-पालन), कृषि मंत्रालय, (कृषि विभाग), नई दिल्ली "
4. पशु पालन निदेशक, उत्तर प्रदेश "
5. मुख्य डैरी विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश सदस्य-  
लखनऊ सचिव

2. यह मूल्य निर्धारण समिति उपरोक्त नियंत्रण आदेश के परिचालन की अवधि के दौरान मेरठ तथा बुलन्दशहर के जिलों के दुग्ध उत्पादकों को दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दिये जाने वाले दुग्ध-मूल्य का निर्धारण करेगी। मूल्य निर्धारण करने में समिति यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि बाजार के प्रचलित रुख के अनुसार दूध उत्पादकों को दुग्ध का उचित मूल्य दिया जाय और उपरोक्त आदेश के प्रख्यापन के फलस्वरूप कृत्रिम परिस्थितियों द्वारा मूल्य पर प्रभाव नहीं पड़े।

3. उत्पादकों को दिये जाने वाले मूल्य के सम्बन्ध में समिति का निर्णय दिल्ली दुग्ध योजना को मानता पड़ेगा।

4. समिति का मुख्यालय मेरठ में होगा। समिति समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथियों पर अपनी बैठके करेगी। उपरोक्त नियंत्रण आदेश के समाप्त होने की तिथि से समिति भंग हो जायेगी।

#### आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति निम्नलिखित को भेजी जाये:—

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
2. सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, सहकारिता (ख) विभाग लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
3. आयुक्त, मेरठ प्रभाग, मेरठ।
4. उप सचिव (पशु-पालन), केन्द्रीय कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष, दिल्ली दुग्ध योजना, नई दिल्ली।
6. पशुपालन निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. मुख्य डेरी विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण की जानकारी के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

मु० ज्यो० मजुमदार, अपर सचिव

#### शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 मई 1971

#### संक्षेप

**विषय :** शैक्षिक योजनाकारी और प्रशासकों के हेतु राष्ट्रीय स्टाफ कालेज नई दिल्ली की स्थापना।

सं० 38-3/71/यू० सू०—विकास के हेतु स्वतंत्रता-पश्चात् प्रयासों ने देश में शिक्षा का स्थिति को पूर्णतः बदल दिया है। पिछले 23 वर्षों के दौरान, शिक्षा का आश्चर्यजनक विस्तार हुआ है जिसका इस देश के पहले के इतिहास में साम्य नहीं है और केवल अधिकांश विकासोन्मुख देशों के समकालीन शैक्षिक इतिहास में कुछ साम्य मिलते हैं। आगामी वर्षों में यह अवश्य ही अधुना रहेगा। शैक्षिक और सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के आपसी प्रभाव से उत्पन्न समस्याएँ, किसी भी पहले के समय की अपेक्षा अधिक चुनौती पूर्ण तथा अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रमाणित होंगी। शैक्षिक प्रशासकों द्वारा इस अभूतपूर्व तथ्य की अब और उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसकी जटिलताओं का उत्तर देने के लिए उन्हें अपने आप को विवेक और निपुणता से तैयार करना पड़ेगा। उनको शिक्षा प्रणाली के व्यापक परिवर्तन के लिए तत्पर रहना चाहिए ताकि इसको युवक वर्ग के जीवन, उनकी आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं और राष्ट्र के तीव्र विकास से निरन्तर संबंध रखा जा सके। अतः वर्तमान और भावी शैक्षिक प्रशासकों का मुख्य कार्य शिक्षा के कार्यक्रमों की योजना बनाना तथा कार्यान्वित करना होगा विशेषकर वे कार्यक्रम—जिनकी निरन्तर गुणात्मक सुधार के लिए अभिकलना की गयी है

अतः यह समय है कि हमारे विकासात्मक कार्यों में शैक्षिक प्रशासन के पुनर्गठन को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। एक नया प्रयास होने के कारण, इसके हेतु सभी संबंधित लोगों अर्थात् केन्द्रीय सरकार, राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों के द्वारा सावधानी से योजनाबद्ध और सतत ध्यान दिये जाने की आवश्यकता होगी। इस संबंध में विस्तृत कार्यक्रमों पर शिक्षा आयोग (1964-66) और शैक्षिक आयोजन प्रशासन तथा मूल्यांकन के कार्यकारी दल द्वारा चर्चा की जा चुकी है। क्योंकि परिवर्तन को ऐसे सभी प्रक्रमों में अनुसंधान और प्रशिक्षण एक निर्णायक भूमिका अदा करते हैं अतः शिक्षा आयोग और शैक्षिक और आयोजन प्रशासन तथा मूल्यांकन के कार्यकारी दल, दोनों ही ने शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के हेतु राष्ट्रीय स्टाफ कालेज की स्थापना करने की सिफारिश की है जो कि शैक्षिक प्रशासन और आयोजन की समस्याओं के संबंध में व्यापक अनुसंधान करेगा, नया परंपराओं के प्रसार के लिए परामर्श और विस्तार सेवाओं का व्यवस्था करेगा तथा उपयुक्त कार्यक्रमों के माध्यम में वरिष्ठ शैक्षिक प्रशासकों के पुनः अनुस्थापन के लिए प्रबंध करेगा। इस सिफारिश को केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन और भारत सरकार ने स्वीकार किया था।

यह अनुभव करते हुए कि राष्ट्रीय स्टाफ कालेज की स्थापना के लिए प्रशासकीय व्यवस्था के साथ-साथ कुछ शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता भी होगी अतः यह निर्णय किया गया कि तत्काल उपलब्ध होने वाले संगठन शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन के एशियाई संस्थान नई दिल्ली का उपयोग किया जाए जो अपने द्वारा संचालित एशियाई कार्यक्रम साथ-साथ एक “भारतीय कार्यक्रम” विकसित करें। यह “भारतीय कार्यक्रम” जो कि मूलतः देश में शैक्षिक प्रशासन की समस्याओं पर और अधिक विचार करने के हेतु प्रोत्साहित देने के लिए बनाया गया है तथा ऐसे कार्यक्रमों का सूत्रपात करने के लिए है जिनसे इनमें से कुछ समस्याओं की गहराई से छानबीन की जा सके। अतः यह, स्टाफ कालेज की समस्या के लिए शैक्षिक पृष्ठभूमि तैयार करने में उपयोगी रहा है। इस अनुभव के आधार पर भारत सरकार ने अब मार्च 1971 से “राष्ट्रीय शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के हेतु स्टाफ कालेज” नामक एक स्वायत्त संगठन की स्थापना करने का निर्णय किया है। फिलहाल, कालेज शैक्षिक आयोजन और प्रशासन के एशियाई संस्थान, नई दिल्ली के अहाते में स्थित है और इस संस्थान के निदेशक, शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के हेतु राष्ट्रीय स्टाफ कालेज के पदेन निदेशक हैं।

भारत सरकार आशा करती है कि स्टाफ कालेज को राज्य सरकारों तथा शैक्षिक संस्थाओं और संगठनों से सहयोग प्राप्त होगा और देश में शैक्षिक आयोजन और प्रशासन के विकास का जो महत्वपूर्ण कार्य इसे सौंपा गया है, यह उसे पूरा कर सकेगा।

टी० पी० मिह, सचिव

#### शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय

#### (शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 जून 1971

सं० एफ० 16-5/68 वाई एस० 1 (3)—शिक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० एफ० 16-5/68 वाई० एस० 1 (3), दिनांक 18 दिसम्बर, 1968 के क्रम में,

श्री टी० डी० रंगा रामानुजम

एन 234, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली-48,

को 14-11-70 से 25-4-71 तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और क्रीड़ा संस्थानों की सोसाइटी के शासी मंडल के एक सदस्य के रूप में उनको व्यक्तिगत हैसियत से मनोनीत किया जाता है।

वी० एन० बहादुर, अवर सचिव

(समन्वय अनुभाग)

नई दिल्ली, दिनांक अप्रैल 1971

सर जमशेदजी जीजीभाई पारसी हितकारी संस्था, बम्बई के विषय में

सं० एफ० 10-1/70 सीडीएन—चूँकि शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 10-1/71-सीडी एन, दिनांक 12 अप्रैल, 1971 द्वारा भारत के पूर्त अक्षय निधि के कोषाध्यक्ष को सर जमशेदजी जीजीभाई पारसी हितकारी संस्था, बम्बई के 39,500 रुपये अंकित मूल्य के 3% प्रथम विकास ऋण 1970-75 से होने वाली भुगतान प्राप्तियों का 6% महाराष्ट्र राज्य विद्युत बंध पत्र, 1981 में पुनर्निवेश करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

क्योंकि भारत के पूर्त-अक्षयनिधि के कोषाध्यक्ष के एजेंट के रूप में पूर्त आयुक्त, महाराष्ट्र, बम्बई ने सूचित किया है कि अब 39,000 रुपये अंकित मूल्य के उपर्युक्त महाराष्ट्र राज्य विद्युत बन्धपत्र, 1981 में 39,488.25 रु० के मूल्य पर रुपया लगाकर के उपर्युक्त पुनर्निवेश पूरा किया जा चुका है तथा अब इस प्रकार 1.75 रु० बाकी बचे हैं जिसका पुनर्निवेश नहीं हो पाया है और यह राशि इतनी कम है कि इसका पुनर्निवेश न हो सकेगा तथा इसलिए इसे उपर्युक्त संस्था के प्राधिकारियों को लौटाया जाना है।

अतः अब पूर्त अक्षय अधिनियम 1890 (1890 का 6) के अनुच्छेद 10 के द्वारा प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के पूर्त अक्षय निधि के कोषाध्यक्ष को निदेश देती है कि 11.75 रुपये (ग्यारह रुपये पचहत्तर पैसे) केवल की बाकी उपर्युक्त राशि, जिसका पुनर्निवेश नहीं ले सका है, सर जमशेदजी जीजी भाई पारसी हितकारी संस्था, बम्बई के प्रशासन में कार्य करने वाले व्यक्ति को लौटा दी जाए।

दिनांक अप्रैल 1971

सर जमशेदजी जीजी भाई पारसी हितकारी संस्था बम्बई के विषय में

सं० एफ० 10-1/70 सीडीएन—चूँकि शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 10-1/70 सीडीएन

तारीख 12 अप्रैल, 1971 के द्वारा भारत के पूर्त अक्षय निधि के कोषाध्यक्ष को सर जमशेदजी जीजीभाई पारसी हितकारी संस्था बम्बई के 11,000 रुपये अंकित मूल्य के 4% बम्बई पत्तन प्रबंध समिति ऋण 1970-71 से होने वाली भुगतान प्राप्तियों का 5% महाराष्ट्र राज्य ऋण, 1982 में पुनर्निवेश करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

क्योंकि भारत के पूर्त अक्षय निधि के कोषाध्यक्ष के एजेंट के रूप में पूर्त आयुक्त महाराष्ट्र, बम्बई ने सूचित किया है कि अब 10,900 रुपये अंकित मूल्य के उपर्युक्त महाराष्ट्र राज्य ऋण 1982 में 10,961.45 रु० के मूल्य पर रुपया जमा करके उपर्युक्त पुनर्निवेश पूरा किया जा चुका है तथा अब इस प्रकार 38.55 रुपये बाकी बचे हैं जिसका पुनर्निवेश नहीं हो पाया है और यह राशि इतनी कम है कि इसका पुनर्निवेश न हो सकेगा। और इसलिए इसे उपर्युक्त संस्था से प्राधिकारियों को लौटाया जाना है।

अतः अब पूर्त अक्षय निधि अधिनियम, 1890 (1890 का 6) के अनुच्छेद 10 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के पूर्त अक्षय निधि के कोषाध्यक्ष को निदेश देती है कि केवल 38.55 रु० (अड़तीस रुपये पचपन पैसे) की बाकी उपर्युक्त राशि, जिसका पुनर्निवेश नहीं हो सका है सर जमशेदजी जीजीभाई पारसी हितकारी संस्था, बम्बई के प्रशासन में कार्य करने वाले व्यक्ति को लौटा दी जाए।

उमा दत्त, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक जून 1971

सं० एफ० 14-6/71-यू०-1—उक्त मंत्रालय की अधिसूचना सं० आर० एम० ए० ई० 5 (12)/53 दि० 21 मई, 1955 के साथ पढ़ी जाने वाली—भारत सरकार पुनर्वासि मंत्रालय की अधिसूचना सं० आर० एच० ए० ई० 11 (5)/52 दि० 5 सितम्बर 1952 की द्वितीय विषय सूची के पैरा 6(घ) में उद्धृत धाराओं के अनुसरण में तथा शिक्षा एवं युवक सेवा मंत्रालय की अधिसूचना सं० एफ० 18-17/63-यू०-1 दि० 12 मार्च, 1970 के द्वारा और संशोधित करते हुए, भारत सरकार श्री विश्व-बन्धु गुप्ता 5 टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली को दि० 8 जनवरी, 1971 से 3 वर्ष की अवधि के लिये देशबन्धु कालेज कालकाजी नई दिल्ली के प्रशासन मंडल के सदस्य के रूप में सहर्ष नामित करती है।

आर० एस० चितकारा, उप-शिक्षा सलाहकार

**PRESIDENT'S SECRETARIAT***New Delhi, the 3rd July 1971*

No. 33-Pres./71.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

*Name and rank of the officer*  
Shri Govinda Appukuttan,  
Constable No. 61110134,  
11th Battalion,  
Central Reserve Police Force.

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

On the morning of 24th December, 1970, a patrol party was directed to search Punglomi Village in Nagaland. After encircling the village, search parties were detailed to comb the houses which were suspected to be the hostile hide-outs. When the Police party consisting of Shri Govinda Appukuttan and seven other constables approached the house of an Ex-Havildar of the hostiles, the inmates of the house shut the door but the Police party forced their entry into the house and started search. During the course of search, Shri Appukuttan found that the inmates were pretending to be sleeping. Shri Appukuttan saw through their trick and pulled their blankets. He then heard a slow bolt manipulation of a rifle under a large basket which was covered with a blanket. He removed the blanket and got hold of a hostile who was hiding under the basket. The hostile pressed his rifle against the chest of Shri Appukuttan but Shri Appukuttan flung the aimed rifle aside and hit the hostile with the butt end of his rifle. He then grappled with the hostile in absolute disregard of his safety. After fierce struggle, Shri Appukuttan snatched his rifle. In this encounter Shri Appukuttan showed courage and determination in apprehending the hostile, who was a prominent hostile leader.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 24th December, 1970.

NAGENDRA SINGH, Secy. to the President

**LOK SABHA SECRETARIAT***New Delhi-1, the 21st June 1971*

No. 5/1/71/PAC.—The following Members of Lok Sabha and Rajya Sabha have been elected to serve as Members of the Committee on Public Accounts for the term ending on 30th April, 1972.

*Members of Lok Sabha*

1. Shri Bhagwat Jha Azad
2. Shrimati Mukul Banerji
3. Shri C. C. Desai
4. Shri K. G. Deshmukh
5. Chaudhari Tayyab Husain Khan
6. Shri Debendra Nath Mahata
7. Shri Mohammad Yusaf
8. Shri B. S. Murthy
9. Dr. Laxminarain Pandey
10. Shri Ramsahai Pandey
11. Shrimati Savitri Shyam
12. Shri Era Sezhiyan
13. Shri Vijay Pal Singh
14. Shri G. Venkatswamy
15. Shri Ram Chandra Vikal

*Members of Rajya Sabha*

16. Shri S. B. Bobdey
17. Shri B. K. Kaul
18. Shri Niranjan Varma (Since resigned from the Committee)
19. Shrimati Vidyawati Chaturvedi
20. Shri Thillai Villalan

21. Shri Shyam Lal Yadav

22. Shri Sheel Bhadra Yajee

2. The Speaker has been pleased to appoint Shri Era Sezhiyan as the Chairman of the Committee.

B. B. TEWARI, Dy. Secy.

*New Delhi-1, the 22nd June 1971*

No. 3/1/ECH/71.—The Speaker has been pleased to appoint Shri Kamal Nath Tewari as Chairman of the Committee on Estimates for the term ending on the 30th April, 1972.

M. S. SUNDARESAN, Dy. Secy.

**CABINET SECRETARIAT****(Department of Personnel)****RULES***New Delhi, the 10th July, 1971*

No. 5/18/71-C.S.(1).—The rules for a limited departmental competitive examination for inclusion in the Select List for the Section Officers' Grade of the Central Secretariat Service to be held by the Union Public Service Commission in 1972 are published for general information.

2. The number of persons to be selected for inclusion in the Select List will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservations shall be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Part C States) Order, 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, and the Constitution (Scheduled Tribes) (Part C States) Order, 1951, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956 read with the Bombay Reorganisation Act, 1960 and the Punjab Reorganisation Act, 1966; the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968 the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968, and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

3. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in the Appendix to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. Any permanent or regularly appointed temporary officer of the Assistants' Grade of the Central Secretariat Service who on the 1st July 1971 satisfies the following conditions, shall be eligible to appear at the examination :—

(1) *Length of Service.*—He should have rendered a continuous service of not than five years in any one or, as the case may be, more than one, of the following posts, namely :—

(i) Assistant (C.S.S.)

(ii) any other post, under the Central Government including the Union Territory Administrations or a State Government, the minimum and the maximum of the scale of pay of which were not less than rupees 160 and rupees 450 respectively in the case of a post held prior to 1st July 1959 and rupees 210 and rupees 530 respectively in the case of a post held on or after 1st July, 1959.

NOTE.—Any permanent or regularly appointed temporary officer of the Assistant Grade of the Central Secretariat Service who joined the Armed Forces during the period of

operation of the Proclamation of Emergency issued on 26th October, 1962, namely 26th October, 1962, to 9th January, 1968, would on reversion from the Armed Forces, be allowed to count the period of his service (including the period of training, if any) in the Armed Forces towards the prescribed minimum service.

- (2) Age.—(a) He should not be more than 40 years of age, i.e., he must not have been born earlier than 1st July, 1931.

Provided that

- (i) any candidate born earlier than 1st July, 1931, but not earlier than 1st July, 1930, who had rendered a continuous service of not less than five years on 1st July, 1970, and
- (ii) any candidate born earlier than 1st July, 1930, but not earlier than 1st July, 1929, who had rendered a continuous service of not less than five years on 1st July, 1969.

in any one or as the case may be more than one of the posts mentioned in Rule 4(1) above, shall also be eligible for admission to this examination as a special case. This relaxation would be admissible for the examination to be held in 1972 only.

NOTE.—The age limit of 40 years will apply to this examination only.

- (b) The age limit prescribed above will be relaxable in the case of a permanent or regularly appointed temporary officer of the Assistants' Grade of the Central Secretariat Service who joined the Armed Forces during the period of operation of the Proclamation of Emergency issued on 26th October, 1962, namely 26th October, 1962, to 9th January, 1968, and who has reverted therefrom, to the extent of the period of his service (including the period of training, if any) in the Armed Forces.
- (c) The age limit prescribed above will be further relaxable :
  - (i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;
  - (ii) up to maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964;
  - (iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964;
  - (iv) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry and has received education through the medium of French at some stage;
  - (v) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;
  - (vi) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;
  - (vii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda or the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);
  - (viii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June 1963;
  - (ix) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(xi) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes; and

(xii) up to a maximum of three years, if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

NOTE 1.—Assistants who are on deputation to *ex-cadre* posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination if otherwise eligible.

This, however, does not apply to an Assistant who has been appointed to an *ex-cadre* post or to another Service on "transfer" and does not have a lien in the Assistants' Grade.

NOTE 2.—Assistants of the Central Secretariat Service who have opted for appointment to the I.F.S. (B) and have been appointed to any grade of that Service in pursuance of such option shall not be eligible for admission to the examination.

NOTE 3.—In the case of a Scheduled Caste Assistant given *ad hoc* promotion with the benefit of "deemed" date of promotion during the period 14th April, 1952 to the 30th April, 1954, his actual date of promotion as Assistant will be taken into consideration for computing the length of service in the Assistants' Grade for the purpose of the above rule.

5. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate to admission from the Commission.

7. A candidate who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall, may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution :—

(a) be debarred permanently or for a specified period by the Commission, from admission to any examination or appearance at any interview held by the Commission for selection of candidates; and

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules.

8. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission to the examination.

9. Candidates must pay the fee prescribed in Annexure I to the Commission's Notice.

10. After the examination, candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for inclusion in the Select List of the Section Officers' Grade up to the required number.

Provided that any candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, who though not qualified by the standard prescribed by the Commission, is declared by them to be suitable for inclusion in the Select List for the Section Officers' Grade with due regard to the maintenance of efficiency of administration shall be recommended for inclusion therein up to the number reserved for members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, as the case may be.

NOTE.—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in the Select List for the Section Officers' Grade on the results of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will therefore, have any claim for inclusion in the Select List on the basis of his performance in this examination, as a matter of right.

11. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

12. Success in the examination confers no right to selection unless Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is eligible and suitable in all respects for selection.

Provided that the decision as to ineligibility for selection in the case of any candidate recommended for selection by the Commission shall be taken in consultation with the Commission.

13. A candidate, who, after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment in the Central Secretariat Service, or otherwise quits the Service or severs his connection with it, or whose services are terminated by his Department, or who is appointed to an *ex-cadre* post or to another service on 'transfer' and does not have a lien in the Assistants' Grade, will be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to an Assistant who has been appointed on deputation to an *ex-cadre* post with the approval of the competent authority.

14. The seniority of candidate who joined the Armed Forces during the period of operation of the Proclamation of Emergency issued on 26th October, 1962, namely 26th October, 1962, to 9th January, 1968, and who could not compete at the Section Officers' Grade Limited Departmental Competitive Examination(s) held during the period of their service in the Armed Forces shall be regulated in accordance with the special orders issued by the Government of India in this behalf, in case they are finally recommended for inclusion in the Select List for the Section Officers' Grade on the results of the examination.

K. L. ARORA, Under Secy.

#### APPENDIX

The examination shall be conducted according to the following plan :—

Part I. Written examination carrying a maximum of 450 marks in the subjects as shown in para 2 below.

Part II. Evaluation of record of service of such of the candidates as may be decided by the Commission in their discretion, carrying a maximum of 150 marks.

2. The subjects of the written examination in Part I, the time allowed and the maximum marks allotted to each paper will be as follows :—

Subject	Maximum Marks	Time allowed
(1) Noting and Drafting Precis-writing	100	2½ hours
(2) Procedure and practice Government of India Secretariat and attached offices	100	2½ hours
(3) General knowledge of the Constitution of India and Machinery of Government; Practice and procedure in Parliament	100	2½ hours
(4) General Financial and Service Rules	50	1½ hours
(5) General Knowledge	100	2½ hours

3. The syllabus for the examination will be as shown in the attached schedule.

Where knowledge of the Rules, orders, instructions, etc., is required candidates will be expected to be conversant with amendments issued up to the date of Notification of this examination.

4. All question papers must be answered in English.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all of the subjects at the examination.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks in the written subjects will be made for illegible handwriting.

9. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

#### SCHEDULE

##### Syllabus of the Examination

(1) Noting and Drafting, Precis Writing.

In addition to questions requiring candidates to prepare notes and drafts on specific problems, passages may also be set for summary or precis.

(2) Procedure and Practice in Government of India Secretariat and attached offices :—

This is intended to be an intensive and detailed test in methods and procedure of work in the Government of India Secretariat and Attached Offices. Some guidance on the subject can be obtained from—

Manual of Office Procedure current at the time of the Notification;

(3) General Knowledge of the Constitution of India and Machinery of Government; Practice and Procedure in Parliament.

NOTE : Knowledge of the following will be expected : (i) the main principles of the Constitution of India; (ii) Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha; and (iii) the organization of the machinery of the Government of India—designation and allocation of subjects between Ministries, Departments, and Attached and Subordinate Offices and their relation *inter se*.

(4) General Financial and Service Rules.

The following books are recommended :—

(i) Fundamental and Supplementary Rules (A.G.P. & Ts. compilation).

(ii) C.S.R. (Pension portion only).

(iii) The Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964.

(iv) The Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.

(v) Compilation of the General Financial Rules (Revised and Enlarged) 1963.

(vi) Compilation of the Delegation of Financial Power Rules, 1958 (with Government of India Decisions) and the Delegation Orders, dated the 1st June, 1962.

(5) General Knowledge.

The paper will cover subjects of interest and importance at the present day. Questions will be set to test knowledge of the broad and salient features of the Five Year Plans and Community Development Schemes, as also intelligent awareness of current affairs, both national and international which an educated person may be expected to have. Candidate's answers are expected to show their intelligent understanding of the questions and not detailed knowledge of any text books, report etc.

[In supersession of the late Ministry of Petroleum & Chemicals and Mines & Metals (Department of Mines & Metals) Resolution No. J-11014/1/70-MI dated 2nd February, 1971]

## MINISTRY OF MINES AND METALS

(Department of Mines)

New Delhi, the 21st June 1971

### RESOLUTION

No. J-11014/1/70-MI.—At the meeting of the Central Geological Programming Board held on 10th September, 1970, it was decided to set up Sub-Committees to go into the various programmes of the Geological Survey of India, other Central Agencies as well as State Departments with reference to Plan objectives in more details. Accordingly the Government of India have decided to set up the following Sub-Committees, the constitution of which is as stated :—

#### I. Sub-Committee on Non-Ferrous Metals

1. Deputy Director General, Geological Survey of India (Shri S. P. Nautiyal)—*Convenor*.
2. Controller, Indian Bureau of Mines.
3. Representative of Hindustan Copper Ltd.
4. Representative of Hindustan Zinc Ltd.
5. Director of Mining & Geology, Rajasthan.
6. Director of Mining & Geology, Andhra Pradesh.
7. Director of Mining & Geology, Mysore.
8. Mining Adviser—Shri I. M. Aga.

#### II. Sub-Committee on Minerals for Iron and Steel Industry (Except Coal)

1. Deputy Director General, Geological Survey of India (Dr. S. V. P. Iyengar)—*Convenor*.
2. Controller, Indian Bureau of Mines.
3. Representative of National Mineral Development Corporation.
4. Director of Mining & Geology, Bihar.
5. Director of Mining & Geology, Madhya Pradesh.
6. Director of Mining & Geology, Orissa.
7. Mining Adviser—Shri I. M. Aga.

#### III. Sub-Committee on Groundwater

1. Deputy Director General, Geological Survey of India (Shri V. Subramanyam)—*Convenor*.
2. Representative of Chief Exploratory Tubewell Organisation.
3. Shri R. N. P. Arogayaswamy, Chief (Minerals) planning Commission.
4. Director of Mining & Geology, Maharashtra.
5. Director of Mining & Geology, Uttar Pradesh.
6. Director of Mining & Geology, Haryana.

#### IV. Sub-Committee on other Minerals

1. Deputy Director General, Geological Survey of India (Shri G. Karunakaran)—*Convenor*.
2. Controller, Indian Bureau of Mines.
3. Director of Mining & Geology, Tamil Nadu.
4. Director of Mining & Geology, Gujarat.
5. Geologist, Directorate of Industries, Punjab, Chandigarh.
6. Director of Geology, Kerala.
7. Mining Adviser, Shri I. M. Aga.

#### V. Sub-Committee on Coal

1. Representative of Director General, Geological Survey of India (Shri B. Laskar) Director, Coal Division—*Convenor*.
  2. Representative of National Coal Development Corporation.
  3. Representative of Central Fuel Research Institute.
  4. Director of Mining & Geology, Bihar.
  5. Director of Mining & Geology, Assam.
  6. Director of Mining & Geology, West Bengal.
  7. Director of Mining & Geology, Madhya Pradesh.
2. The functions of each Sub-Committee would be :—
- 2(i) to review the work done so far relating to the exploration of minerals in the country;

(ii) to go into the various programmes of Geological Survey of India, other Central Agencies as well as State Departments;

(iii) to recommend changes in priorities assigned to the various items of work, if necessary; and

(iv) to advise the Government from time to time on the various urgent matters of policy and execution.

3. The Sub-Committees shall have the power to coopt other members to the extent they feel necessary during their deliberations (including the members of other Sub-Committees to the extent it is felt desirable).

4. In subsequent years the composition of the Sub-Committees could be suitably changed by rotation as also by giving representation to new interests if it becomes necessary after watching the work of the Sub-Committees next year.

5. The Sub-Committees shall make available to the Department of Mines their reports well in advance of the meeting of the Central Geological Programming Board.

6. This supersedes the earlier Resolution No. J-11014/1/70-MI, dated 2-2-1971.

### ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all concerned including the Ministries of the Government of India, all the State Governments, Union Territories, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, the Department of Parliamentary Affairs and the Planning Commission.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

T. N. LAKSHMINARAYANAN, Jt. Secy.

## MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

New Delhi, the 14th June 1971

### RESOLUTION

No. 33(7)/71-L.Con.Ind.—The Government of India have decided to reconstitute the Panel for the Air-conditioning and Refrigeration Industry with the object of examining and advising the Government of India on special measures necessary for planning the growth and development of this Industry as also for considering the various problems faced by the manufacturers in this field. The composition of the Panel will be as follows :—

#### Chairman

1. Shri V. P. S. Menon, Industrial Adviser, D.G.T.D., New Delhi.

#### Member-Secretary

2. Shri D. B. Malik, Development Officer, D.G.T.D., New Delhi.

#### Members

3. Shri S. Raghaviah, Director, Office of the DC(SS), New Delhi.
4. Shri N. N. Agrawala, Joint Director, Planning Commission, New Delhi.
5. Shri Surendra M. Mehta, Director, Air Control & Chemical Engineering Co. Ltd., Reghuvanshi Mills Compound, 11-12, Haines Road, Bombay-13.
6. Shri Ram D. Malani, Executive Director, Blue Star Limited, Jamshedji Tata Road, Bombay-20.
7. Shri P. D. Gune, Chief Executive (Operations) M/s. Kirloskar Brothers Ltd., Kirloskarvadi, District Sangli, Maharashtra.
8. Shri J. C. Kapur, Director, M/s. Danfoss (India) Limited, B-20/21, Industrial Area, Site No. 3, Meerut Road, P.B. No. 6, Ghaziabad.
9. Shri M. C. Gupta, M/s. Shriram Refrigeration Industries Ltd., Balanagar Township, Hyderabad-37.
10. Shri Manmohan Singh, Managing Director, M/s. Frick India Limited, Jeevan Vihar, 3-Parliament Street, Post Box 118, New Delhi-1.



11. Shri J. Desai, Managing Director, M/s. Kalvinator of India Ltd., 28, New Industrial Town Faridabad.
12. Shri V. P. Punj, M/s. Fedders Lloyd Corporation Pvt. Ltd., Punj House, M-13, Connaught Circus, New Delhi-1.
13. Shri O. P. Bhartia, Deputy Managing Director, M/s. Cutler-Hammer India Ltd., 20/4, Mathura Road, Faridabad-11.
14. Shri B. S. Dua, M/s. American Refrigerator Co. Ltd., 12-D, Park Street, Calcutta-16.
15. Shri H. J. Sponner, Managing Director, M/s. S. F. India Limited, Post Box 411, Calcutta-1.
16. Shri N. Balasubramanian, M/s. Voltas Limited, 19, Graham Road, Bombay-1.
17. Shri Gajindra Singh, M/s. Oriental Refrigeration & Engineering Co. Private Ltd., Lakshmi Building, 1st Floor, Asaf Ali Road, P.O. Box No. 563, New Delhi-1.
18. Shri G. K. Kabra, Chief Engineer, M/s. Hyderabad Allwyn Metal Works, Ltd., Sanatnagar, Hyderabad-18.
19. Shri Amer P. Sur, M/s. Sur Industries Pvt. Ltd., 163, Lower Circular Road, Calcutta.
20. Shri Ramesh Anand, M/s. Chandra Industries, G. T. Road, Jullundur.
21. Deputy Director of Inspection, Customs and Central Excise, Ministry of Finance, Department of Revenue & Insurance, New Delhi.
22. One Representative of Ministry of Food & Agriculture (Department of Food), New Delhi.
23. Shri M. V. Patankar, Director (Mech. Engg.), Indian Standards Institution, Manak Bhavan, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi.
24. One Representative of Central Mechanical Engineering Research Institute, Durgapur.

2. The terms of the Panel will be for a period of two years.

#### ORDER

ORDERED that copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

R. K. TALWAR, Jt. Secy.

#### MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, C.D. & COOPERATION

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 13th May 1971

#### RESOLUTION

No. 30-1/71-L.D.III.—In continuation of this Ministry's Resolution No. 30-1/71-L.D.III, dated the 2nd February, 1971 and in partial modification of this Ministry's Resolution No. 20-20/69-L.D.III, dated 26/29-11-69, the Government of India have decided that the date upto which the Director of Administration, Directorate of Extension may operate on the current account of the Central Council of Gosamvardhana be further extended from the 31st March, 1971 to 31st July, 1971 or till the pending claims are settled, whichever is earlier.

#### ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments, Administration of Union Territory and the Department of the Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. P. GULATI, Dy. Secy.

New Delhi, the 19th June 1971

#### RESOLUTION

No. 19-9/1-L.D.I. Consequent on the promulgation of the Delhi, Meerut and Bulandshahr Milk and Milk Products Control Order 1971, the Government of India have decided to constitute a Price Fixation Committee for the duration of the Order i.e. from 7th May 1971 to 15th July 1971 with the following membership :—

#### Chairman

- (1) Commissioner, Meerut Division.

#### Members

- (2) Chairman, Delhi Milk Scheme.
- (3) Deputy Secretary (Animal Husbandry) Ministry of Agriculture (Department of Agriculture) New Delhi.
- (4) Director of Animal Husbandry, U.P.

#### Member Secretary

- (5) Chief Dairy Development Officer, U.P., Lucknow.

2. The Price Fixation Committee shall determine the price of the milk to be paid by the Delhi Milk Scheme to the Milk producers of the districts of Meerut and Bulandshahr during the operation of the Control Order mentioned above. In determining the price, the Committee will try to ensure that the milk producers will be paid a fair price for milk in line with the prevailing market trend and that the price will not be affected by the artificial conditions resulting from the promulgation of the Order referred to above.

3. The decision of the Committee as regards the price payable to the producers shall be binding on the Delhi Milk Scheme.

4. The headquarters of the Committee will be at Meerut. The Committee may meet periodically on such dates as may be decided by the Chairman. The Committee will stand dissolved on the date of the expiry of the Control Order mentioned above.

#### ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to :—

- (1) Chief Secretary, Government of U.P., Lucknow.
- (2) Secretary to Government of U.P., Cooperative(B) Department, Lucknow (U.P.).
- (3) Commissioner, Meerut Division, Meerut.
- (4) Deputy Secretary (Animal Husbandry), Union Ministry of Agriculture (Department of Agriculture), Krishi Bhavan, New Delhi.
- (5) Chairman, Delhi Milk Scheme, New Delhi.
- (6) Director of Animal Husbandry, U.P., Lucknow.
- (7) Chief Dairy Development Officer, U.P., Lucknow.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. J. MAJUMDAR, Addl. Secy.

#### MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE

New Delhi, the 19th May 1971

#### RESOLUTION

SUBJECT :—Establishment of National Staff College for Educational Planners and Administrators, New Delhi.

No. F. 38-3/71-UU.—The post-independence effort towards development has entirely changed the educational scene in the country. During the last 23 years, there has been a tremendous expansion of education which has had no parallel in the earlier history of this country and only a few parallels in the contemporary educational history of most developing countries. In the years ahead, it is bound to continue unabated. The problems generated by the mutual impact of educational and socio-economic changes would prove to be far more challenging and of deeper significance than they were at any earlier time. This unprecedented

phenomenon of change can no longer be ignored by educational administrators. They have to prepare themselves to respond to its intricacies with understanding and skill. They have to be ready for a comprehensive transformation of the educational system so as to keep it continually relevant to the life, needs and aspirations of the young people and the rapid development of the nation. The chief concern of the educational administrator of today and tomorrow, therefore, would be to go on planning and implementing programmes of education, and particularly those designed for its ceaseless qualitative improvement.

It is time, therefore, that reorganisation of educational administration receives priority among our developmental tasks. Being a new venture, it will need carefully planned and sustained attention on the part of all concerned—the Central Government, the States and the Union Territories. Broad programmes have been discussed in this connection by the Education Commission (1964-66) and by the Working Party on Educational Planning, Administration and Evaluation (1969). Since research and training play a crucial role in all such processes of transformation, both the Education Commission and the Working Party on Educational Planning, Administration and Evaluation, recommended the setting up of a National Staff College for Educational Planners and Administrators, which would undertake extensive research in the problems of educational administration and planning, provided consultancy and extension services for diffusion of new practices, and arrange for the reorientation of senior educational administrators through suitable programmes. This recommendation was accepted by the Central Advisory Board of Education, the State Education Minister's Conference and the Government of India.

Realising that the establishment of the National Staff College would require certain academic facilities as well as an administrative set up, it was decided to utilize the readily available organization of the Asian Institute of Educational Planning and Administration, New Delhi, to develop an 'Indian Programme' alongside the 'Asian Programmes' it has been conducting. This 'Indian Programme', essentially designed for stimulating further thinking on problems of educational administration in the country, and initiating activities which would explore some of these problems in depth, has been useful in preparing the academic background for the establishment of the Staff College and based on this experience, the Government of India have now decided to establish, with effect from March 1, 1971, an autonomous organisation, named as the "National Staff College for Educational Planners and Administrators". For the present, the College is located in the premises of the Asian Institute of Educational Planning and Administration, New Delhi and the Director of the Institute is the *ex-officio* Director of the National Staff College for Educational Planners and Administrators.

The Government of India hope that the Staff College will receive co-operation from State Governments and Educational Institutions and organisations, and would be able to fulfil the important task of improvement of educational planning and administration in the country, with which it has been entrusted.

T. P. SINGH, Secy.

(Department of Education)

New Delhi, the 3rd June 1971

No. F.16-5/68YSI(3).—In continuation of the Ministry of Education Notification No. F.16-5/68YSI(3), dated 18th December, 1968,

Shri T. D. Ranga Ramanujan, N-234, Greater Kailash, New Delhi-48,

is nominated, in his individual capacity, as a Member of the Board of Governors of the Society for the National Institutes of Physical Education and Sports for the period from 14-11-70 up to 25-4-71.

V. N. BAHADUR, Under Secy.

(Coordination Section)

New Delhi, the 24th June 1971

IN THE MATTER OF SIR JAMSETJEE JEJEEBHOOY  
PARSEE BENEVOLENT INSTITUTION BOMBAY

No. F.10-1/70-CDN.—Whereas by Office Memorandum No. 10-1/70-CDN, dated the 12th April, 1971 from the Ministry of Education and Youth Services, the Treasurer of Charitable Endowments for India was authorised to re-invest the repayment proceeds of the 3% 1st Development Loan 1970-75 of the face value of Rs. 39,500/- belonging to the Sir Jamsetjee Jejeebhoy Parsee Benevolent Institution, Bombay in the 6% Maharashtra State Electricity Bonds 1981;

And whereas the Charity Commissioner, Maharashtra, Bombay as agent of the Treasurer of Charitable Endowments for India has reported that the said re-investment has since been completed by subscribing to the said Maharashtra State Electricity Bonds 1981 of the face value of Rs. 39,000/- at a cost of Rs. 39,488.25, thus leaving an un-invested balance of Rs. 11.75, which is too small an amount for investment and has, therefore, to be refunded to the authorities of the said Institution;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 10 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890) the Central Government hereby directs the Treasurer Charitable Endowments for India to refund the said un-invested balance of Rs. 11.75 (Rupees eleven and paise seventy-five), only to the person acting in the administration of the Sir Jamsetjee Jejeebhoy Parsee Benevolent Institution, Bombay.

No. F. 10-1/70-CDN.—Whereas by Office Memorandum No. F. 10-1/70-CDN, dated the 12th April, 1971 from the Ministry of Education and Youth Services, the Treasurer of Charitable Endowments for India was authorised to re-invest the repayment proceeds of the 4% Bombay Port Trust Loan 1970-71 of the face value of Rs. 11,000/- belonging to the Sir Jamsetjee Jejeebhoy Parsee Benevolent Institution, Bombay in the 5½% Maharashtra State Loan, 1982;

And whereas the Charity Commissioner, Maharashtra, Bombay, as agent of the Treasurer of Charitable Endowments for India reported that the said re-investment has since been completed by subscribing to the said Maharashtra State Loan 1982 of the face value of Rs. 10,900/- at a cost of Rs. 10,961.45 thus leaving an un-invested balance of Rs. 38.55, which is too small an amount for investment and has, therefore, to be refunded to the authorities of the said Institution;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 10 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890) the Central Government hereby directs the Treasurer Charitable Endowments for India to refund the said un-invested balance of Rs. 38.55 (Rupees thirty eight and paise fifty five), only to the person acting in the administration of the Sir Jamsetjee Jejeebhoy Parsee Benevolent Institution, Bombay.

UMA DATT, Under Secy.

New Delhi, the June 1971

No. F. 14-6/71-U.1.—In pursuance of the provisions contained in paragraph 6(d) of the second schedule to the Government of India, Ministry of Rehabilitation Notification No. RHE/11(5)/52, dated the 5th September, 1952, read with the notification No. RHA/5(12)/53, dated the 21st May, 1955 of the aforesaid Ministry and as further amended vide notification No. F. 18-17/63, U.1, dated the 12th March, 1970 of the Ministry of Education and Youth Services the Government of India are pleased to nominate Shri Vishwa Bandhu Gupta, 5, Tolstoy Marg, New Delhi to be a member of the Board of Administration of the Deshbandhu College, Kalkaji, New Delhi for a term of three years with effect from 8th January, 1971.

R. S. CHITKARA, Dy. Educational Adviser